नकारात्मक ब्याज दर

सन्दर्भ

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के नीति निर्धारक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उच्च मुद्रास्फीति बढ़ रही हैं। मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ने पर ईसीबी ने पिछले महीने दरों को 50 आधार अंक बढ़ाकर शून्य कर दिया था।

प्रमुख बिंदु

- यूरोपीय सेंट्रल बैंक और डेनमार्क, जापान, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड के केंद्रीय बैंकों ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जारी कमजोर विकास का मुकाबला करने के लिए नकारात्मक ब्याज दरों के साथ प्रयोग किया था।
- आम तौर पर, किसी को पैसे या बचत का उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ता है। प्राचीन संस्कृत में प्रयोग से लेकर आधुनिक अंग्रेजी में इंटरेस्ट तक, इसे कई अलग-अलग शब्दों से जाना जाता है।
- संस्थागत, कानूनी ब्याज दर का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण एश्नुन्ना के कानून में मिलता है, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व का एक प्राचीन बेबीलोनियाई पाठ है।

नीति दर, आर्थिक चक्र और ब्याज की तटस्थ दर

- केंद्रीय बैंक आर्थिक चक्र में बदलाव और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नीतिगत दरों में बदलाव करते हैं।
- नीतिगत दर निर्धारित करने में केंद्रीय बैंकरों के लिए एक मार्गदर्शक पद तटस्थ ब्याज दर की अवधारणा है: दीर्घकालिक ब्याज दर जो स्थिर मुद्रास्फीति के अनुरूप है।
- तटस्थ ब्याज दर न तो आर्थिक विकास को प्रेरित करती है और न ही रोकती है। जब ब्याज दरें तटस्थ दर से कम होती हैं, तो मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है, और जब वे अधिक होती हैं, तो यह संकुचनकारी होती है।

नकारात्मक आईआर - अर्थ और निहितार्थ

- नकारात्मक ब्याज दरें मौद्रिक नीति का एक रूप है जिसमें ब्याज दरों में 0% से नीचे की गिरावट देखी जाती है।
- केंद्रीय बैंक और नियामक इस असामान्य नीति उपकरण का उपयोग तब करते हैं जब अपस्फीति के मजबूत संकेत होते हैं।
- ऋणदाताओं को ऋणात्मक ब्याज दर परिवेश में ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान करने के बजाय ब्याज क्रेडिट किया जाता है।
- केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नकदी की स्थिति को जमा करने के बजाय खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में भंडार पर शुल्क लगाते हैं।
- अधिक व्यापक नकारात्मक दर के माहौल के मामले में, बचतकर्ताओं को इसे प्राप्त करने के बजाय ब्याज का भुगतान करना होगा।

बैंकों पर प्रभाव

- जब दरें शून्य से नीचे चली जाती हैं, तो बैंक इस डर से अपने जमाकर्ताओं को ऋणात्मक ब्याज दरें देने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं कि वे अपनी जमा राशि वापस ले लेंगे।
- यदि बैंक जमाराशियों पर ऋणात्मक दरों से परहेज करते हैं, तो यह सैद्धांतिक रूप से प्रसार (जमाकर्ताओं को जो भुगतान करते हैं और ऋण पर वे जो शुल्क लेते हैं, के बीच अंतर) को नकारात्मक रूप से बदल सकते हैं, क्योंकि ऋण पर प्रतिफल जमाराशियों की लागत को कवर नहीं करेगा।
- यह बदले में बैंक की लाभप्रदता को कम कर सकता है और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को कमजोर कर सकता है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक+)

सन्दर्भ

ओपेक+ के सदस्य सऊदी अरब के इस विचार के समर्थन में सामने आए हैं कि विश्व तेल बाजारों को स्थिर करने के लिए आपूर्ति प्रतिबंधों की आवश्यकता हो सकती है।

ओपेक के बारे में

- ओपेक एक स्थायी, अंतरसरकारी संगठन है, जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10-14 सितंबर, 1960 को बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था।
- ओपेक का उद्देश्य है:

पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना;
उपभोग करने वाले राष्ट्रों को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति;
उद्योग में निवेश करने वालों को पूंजी पर उचित प्रतिफल।

- 1960 के दशक में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में "सेवन सिस्टर्स" बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व था।
- इसका सचिवालय वियना में स्थित है।
- वर्तमान में, संगठन के कुल 13 सदस्य देश : ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबॉन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो हैं।

ओपेक+ . के बारे में

- ओपेक+ ओपेक के 13 सदस्यों और अन्य गैर-ओपेक सदस्यों को संदर्भित करता है।
- गैर-ओपेक सदस्य रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको, ओमान, बहरीन, ब्रुनेई, दक्षिण सूडान, सूडान और मलेशिया हैं।
- ये राष्ट्र ओपेक और गैर ओपेक उत्पादक देशों के बीच सहयोग के लिए एक ढांचे को संस्थागत बनाने के लिए 2016 के अंत में एक समझौते पर आए।
- ओपेक दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है, गैर-ओपेक सदस्यों के साथ वैश्विक तेल का कुल हिस्सा आधे से भी कम है।
- यू.एस., चीन या यू.के., कनाडा और नॉर्वे जैसे ऊर्जा के अन्य प्रमुख पश्चिमी उत्पादक समूह का हिस्सा नहीं हैं।

अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला

सन्दर्भ

भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले आकार में 10 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- यह पहले से मौजूद निवासी अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने और पहचानने की प्रभावशीलता में सुधार करेगा, और इसके परिणामस्वरूप एक हाइब्रिड डेटा पूल का निर्माण होगा जो अंतरिक्ष उद्योग के वाणिज्यिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों की सेवा करेगा।
- स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (एसएसए) वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल हैं।
- वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका कई स्थानों पर वेधशालाओं और दुनिया भर से अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने वाली वाणिज्यिक कंपनियों के साथ अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में एक प्रमुख खिलाड़ी है।
- उच्च-गुणवत्ता वाले अवलोकन, इसके साथी ग्राउंड-आधारित सेंसर नेटवर्क के साथ, गहरे अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं , विशेष रूप से भूस्थिर, मध्यम-पृथ्वी और उच्च-पृथ्वी की कक्षाओं में की निगरानी करने की क्षमता में सुधार करने में मदद करेंगे, ।
- इस डेटा के साथ, यह उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान के बीच टकराव की संभावना को उनके स्थान, गति और प्रक्षेपवक्र की अधिक सटीक भविष्यवाणी करके कम करने में सक्षम होगा।
- वेधशाला भारत को उपमहाद्वीप में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने की स्वदेशी क्षमता भी देगी।
- यह सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए देश में स्वदेशी क्षमताओं को भी लाएगा।
- यह पहले से मौजूद निवासी अंतरिक्ष वस्तुओं (आरएसओ) को ट्रैक करने और पहचानने की प्रभावशीलता में सुधार करेगा, और इसके परिणामस्वरूप एक हाइब्रिड डेटा पूल का निर्माण होगा जो अंतरिक्ष उद्योग के वाणिज्यिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों की सेवा करेगा।

लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा

सन्दर्भ

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने लद्दाख में पृथ्वी की आंतों से ऊर्जा की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी है - एक ऐसा क्षेत्र जो हिमालयी भू-तापीय बेल्ट पर स्थित है। यह भारत की पहली भू-तापीय ऊर्जा परियोजना होगी और 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना भी होगी।

हिमालयी भूतापीय बेल्ट

- भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ और भारी मात्रा में ताप उत्पन्न हुआ जो चट्टानों के नीचे फंस गया।
- परिणामी हिमालयी भूतापीय बेल्ट भारत के कुछ हिस्सों से तिब्बत, चीन (युन्नान) तक और म्यांमार और थाईलैंड से होकर गुजरती है।
- माना जाता है कि 150 मीटर चौड़े क्षेत्र में 3000 किमी लंबाई में सैकड़ों भू-तापीय क्षेत्र हैं जो बिजली उत्पादन कर सकते हैं।
- लद्दाख के कुछ हिस्सों ने गर्म झरनों, मिट्टी के पूल, सल्फर और बोरेक्स जमा के रूप में भू-तापीय गतिविधि के प्रमाण दिखाए हैं।
- दो महाद्वीपीय प्लेटों के संगम पर लद्दाख की स्थिति और नदियों और अन्य जल स्रोतों की उपलब्धता इस जगह को भूतापीय बिजली उत्पादन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाती है।
- लद्दाख के पुगा में उपसतह का तापमान बहुत अधिक है।
- भूतापीय जलाशयों को उनके तापमान की विशेषता होती है, क्योंकि यह जितना अधिक गर्म होता है, उतनी ही अधिक ऊर्जा चट्टानों में फंस जाती है और भाप के रूप में निकलने वाले पानी का उपयोग टर्बाइनों को चालू करने के लिए किया जा सकता है।

मनुस्मृति

सन्दर्भ

हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मनुस्मृति में लैंगिक भेद को लेकर आलोचना की।

मनुस्मृति क्या है?

- मानवधर्मशास्त्र, जिसे मनुस्मृति या मनु के नियमों के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र साहित्यिक परंपरा से संबंधित एक संस्कृत पाठ है।
- दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी सीई के बीच कभी-कभी रची गई, मनुस्मृति श्लोक छंदों में लिखी गई है, जिसमें प्रत्येक 16 पाठ्यक्रम की दो गैर तुकबंदी वाली पंक्तियाँ हैं।
- पाठ को मनु की पौराणिक आकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसे हिंदू धर्म में मानव जाति का पूर्वज माना जाता है।
- पाठ के लेखकत्व पर विद्वानों के बीच काफी बहस हुई है। कई लोगों ने तर्क दिया है कि इसे कई ब्राह्मण विद्वानों द्वारा एक समय में संकलित किया गया था।
- मनुस्मृति का दायरा विश्वकोश है, जिसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है:
  - जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न जातियों और व्यक्तियों के सामाजिक दायित्व और कर्तव्य,
  - विभिन्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं के उपयुक्त सामाजिक और यौन संबंध,
  - करों पर,
  - राजत्व के नियम,
  - वैवाहिक सद्भाव बनाए रखने और रोजमर्रा के विवादों को निपटाने की प्रक्रिया पर
- यह 1794 में ब्रिटिश भाषाशास्त्री सर विलियम जोन्स द्वारा यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला पहला संस्कृत पाठ था।
- ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए, पुस्तक के अनुवाद ने एक व्यावहारिक उद्देश्य पूरा किया।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग

सन्दर्भ

भारत और बांग्लादेश के मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग, जेआरसी की 38वीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- दोनों पक्षों ने 'कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे' पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया।

- दोनों पक्षों ने इस विषय पर अक्टूबर 2019 के भारत-बांग्लादेश समझौता ज्ञापन के अनुसार, त्रिपुरा के सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनी नदी पर पानी के सेवन बिंदु के डिजाइन और स्थान को अंतिम रूप देने का भी स्वागत किया।
- भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें से सात नदियों को प्राथमिकता के आधार पर जल बंटवारे समझौतों की रूपरेखा विकसित करने के लिए पहले ही पहचाना जा चुका है।
- बैठक के दौरान आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए आठ और नदियों को शामिल कर चल रहे सहयोग के क्षेत्र को व्यापक बनाने पर सहमति बनी।
- भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में किया गया था।

भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस

सन्दर्भ

केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को सीएसआईआर - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केपीआईटी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।

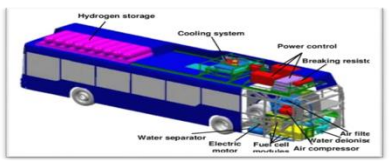

- 'हाइड्रोजन विजन' का उद्देश्य भारत को मौसम परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने, स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) बनाना है।
- ईंधन सेल बिजली पैदा करने और बस को बिजली देने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है। यदि एक डीजल बस की तुलना की जाए, तो यह आमतौर पर लंबी दूरी के मार्गों पर प्रति वर्ष 100 टन CO_2 उत्सर्जित करती है।
- हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रकों की परिचालन लागत डीजल बसों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है और यह पूरे देश में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू) उपकर

सन्दर्भ

तिरुपति में आयोजित राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में, प्रधान मंत्री ने राज्यों से निर्माण श्रमिकों के उपकर का पूरा उपयोग करने के लिए कहा जो उनके लिए प्रदान किया गया था और अभी भी रुपये 38,000 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया था।

यह क्या है?

• यह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार एक नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर 1% की दर से लगाया जाने
वाला उपकर है।

• यह सूची - I, संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत आता है, अनुसूची VII में सूची III के क्रम 23 और 24 में प्रविष्टि के साथ पढ़ा जाता है।

• भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18(1) के तहत गठित कल्याण बोर्ड को कामगारों को स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपायों का प्रावधान सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

• एकत्र की गई राशि उसके संग्रहण के तीस दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अधिनियम के तहत "भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष" बनाया गया है। सेस के रूप में लगाया और एकत्र किया गया फंड फंड में जमा किया जाता है।

अफ्रीका और भारत की ऋण सहायता

सन्दर्भ

कई अफ्रीकी देशों ने भारत से अपने विकास ऋणों (लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी) के हिस्से की सेवा की पेशकश के साथ भारतीय कंपनियों को उनके खनन कार्यों में पहुंच प्रदान करके और अत्यधिक बेशकीमती लिथियम और कोबाल्ट के निर्यात की अनुमति देकर संपर्क किया है।

प्रमुख बिंदु

• भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS) के तहत रियायती नियंत्रण रेखा के माध्यम से भारत विकास सहायता प्रदान करता है।

• दृष्टिकोण भारत द्वारा लाभ उठाने वाले आर्थिक व्यापार-बंद का पहला ऐसा उदाहरण है।

• कुल मिलाकर, 32 अरब डॉलर मूल्य के 300 से अधिक एलओसी को भारत ने दुनिया भर के 65 देशों में विस्तारित किया है।

• अफ्रीका के साथ, भारत ने $12 बिलियन से अधिक मूल्य के 41 से अधिक देशों में एलओसी का विस्तार किया है।

• एलओसी का विस्तार एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है और प्रत्येक एलओसी के अंतर्गत कई परियोजनाएं हो सकती हैं। अफ्रीकी देशों के साथ एलओसी सौदा भारत को मैग्नीशियम, निकल, जस्ता, सीसा, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, एल्यूमिना, लोहा, तांबा और बॉक्साइट जैसे खनिज और धातु अयस्कों तक पहुंच प्रदान कर सकता है।

• अफ्रीका के अलावा, भारत मध्य एशियाई देशों, बोलीविया और रूस के साथ पुनर्गठित नियंत्रण रेखा व्यवस्था का पता लगा सकता है। भारत ने 2020 में रूस को $1BN LoC का विस्तार किया था।

दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर ट्रेन

सन्दर्भ

दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कोराडिया आईलिंट, जर्मनी के लोअर सैक्सोनी में शुरू हुई।

मुख्य बिंदु

• अब तक की पहली रेल लाइन पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों पर चलेगी।

• चौदह हाइड्रोजन ट्रेनें ईंधन सेल प्रणोदन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होती हैं।

• ट्रेनें उत्सर्जन मुक्त और कम शोर वाली हैं, जिनमें केवल भाप और निकास से गाढ़ा पानी निकलता है। उनके पास 1,000 किलोमीटर की सीमा है जिसका अर्थ है कि वे पूरे दिन नेटवर्क पर हाइड्रोजन के एक टैंक पर चल सकते हैं।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare